# सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 5 | 7 मार्च से 21 मार्च 2026 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1


## महान जे.वी. स्तालिन जिन्दाबाद

21 दिसम्बर 1879–5 मार्च 1953

"मार्क्सवाद महज समाजवाद का सिद्धान्त ही नहीं है, बल्कि यह एक सुसंहत विश्व दृष्टिकोण, एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली भी है, जिससे मार्क्स का सर्वहारा समाजवाद तर्कसंगत ढंग से आ जाता है। इस दार्शनिक प्रणाली को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है।" (अराजकतावाद या समाजवाद, 1906)

"लेनिनवाद है साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद। बल्कि यह कहना अधिक सटीक होगा कि लेनिनवाद सामान्य रूप से सर्वहारा क्रांति का और विशेष रूप से सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का सिद्धांत और कार्यनीति है।" (लेनिनवाद के मूल सिद्धांत)

"पूरी मानव जाति अमीर और गरीब, संपत्ति के मालिकों और शोषितों में विभाजित है और इस बुनियादी बंटवारे के बारे में, गरीब और अमीर के बीच विरोध के बारे में खुद को झूठलावे में रखने का मतलब है खुद को बुनियादी सच्चाई के बारे में झूठलावे में रखना।" (एचजी वेल्स के साथ साक्षात्कार, सितंबर, 1937)

## केंद्रीय बजट 2026 —सब कर्तव्य और संकल्प
## बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए, आम लोगों की कोई चिंता नहीं

केंद्र की भाजपाई वित्त मंत्री ने 26-27 के अपने बजट भाषण में कहा: "12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला, तब से, भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और कम मुद्रास्फीति से चिह्नित रहा है। यहां तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी, हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के फलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और निरंतर, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है।" फिर उन्होंने कहा: "हमारी सरकार का 'संकल्प' हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है।" उन्होंने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए, बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। पिछले साल, भाजपाई वित्त मंत्री ने "विकसित भारत" यानी 2047 तक एक विकसित भारत के नारे से शुरुआत की थी। बातें बहुत बड़ी-बड़ी थीं। फिर भी, ठंडे दिमाग से मैक्रोइकोनॉमिक्स के आंकड़ों के विश्लेषण से 2032 तक कोई बड़ी कामयाबी (अपर-मिडिल-इनकम वाली अर्थव्यवस्था की तरफ) नहीं, बल्कि एक छोटे, सबको अलग रखने वाले विकास मॉडल का मजबूत होना पता चलता है, जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना देगा। भाषण में पारदर्शिता नहीं थी, क्योंकि इसमें खास कार्यक्रम और योजना के लिए बजट में किये गए आवंटन का कोई आइडिया नहीं दिया गया था। परिशिष्ट से नंबर निकालकर आंकड़े निकालने पड़े।

असल में, पूरा बजट, जो अब असलियत से ज्यादा ही रस्म अदायगी वाला हो गया है, सिर्फ ज्यादा वादे और कम काम करने का चालाकी भरा दिखावा है।

**कमाई वाला पहलू**

थोड़े विस्तार में जाने से पहले, आइये, एक जरूरी बात पर ध्यान दें। बजट में लोगों को यह जानना जरूरी है कि सरकार के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है और वह पैसा कहां से आ रहा है। बजट 26-27 कुल 53.47 लाख करोड़

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : देश की जनता को व्यवहारतः अंधेरे में रखा गया

साम्राज्यवाद के मौजूदा दौर में 'मुक्त व्यापार' जैसा कुछ नहीं होता है; किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ रिश्ता कैसा है, कौन किसे अपना करीबी दोस्त बताता है या मिलने पर कितनी गर्मजोशी से गले लगाता है–इनमें से किसी बात से भी व्यापारिक रिश्ता तैयार नहीं होता है, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसकी सबसे सटीक मिसाल है।

दरअसल, जिसके पास पूंजी की ताकत जितनी ज्यादा होती है, वह उतने ही बड़े नियंत्रक की भूमिका में होता है। भारत-अमेरिका समझौते में अमेरिका की भूमिका नियंत्रक की ही है। यही वजह है कि किसी संयुक्त घोषणा की बजाय, समझौते की हर बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही की। यहां तक कि भारत किन चीजों को खरीदने के लिए तैयार हुआ है, यह भी ट्रंप ने ही बता दिया। समझौते में अमेरिका के सामने भारत का आत्मसमर्पण पूरी तरह से स्पष्ट है। हालांकि इस समझौते की वजह से भारतीय किसानों सहित बहुसंख्यक मेहनतकश अवाम को भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन इससे देश के एकाधिकारी पूंजीपतियों को फायदा होगा। आइए, मामले की तह में जाते हैं। पहले भारत के साथ भारी व्यापार घाटे को रोकने के लिए 25 प्रतिशत और बाद में रूस से तेल आयात के बहाने और 25 प्रतिशत–कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) थोप दिया था। इससे देश के उद्योग जगत में हाहाकार मच गया, क्योंकि भारतीय निर्यात का 18 प्रतिशत अमेरिका जाता है, जो विदेशों में होने वाले कुल निर्यात में सबसे ज्यादा है। इसके बाद लम्बी सौदेबाजी हुई, जो दरअसल भारत पर अमेरिकी पूंजी के दबाव के अलावा और कुछ नहीं थी। आखिरकार 18 प्रतिशत शुल्क स्वीकार कर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और भारत 50,000 करोड़ डॉलर की वस्तुएं और सेवाएं अमेरिका से खरीदने के लिए 'प्रतिबद्ध' होने का लिखित आश्वासन देने पर मजबूर हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका से भारत में केवल 4180 करोड़ डॉलर का माल आयात किया गया है। दूसरी ओर, भारत ने अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और वहां के खाद्य एवं कृषि उत्पादों के एक बड़े हिस्से पर या तो आयात शुल्क हटा दिया है या काफी घटा दिया है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क का दबाव बनाकर भारतीय बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खुलवाना ही ट्रंप की इस शुल्क-धमकी का मुख्य उद्देश्य था।

**अमेरिका से भारत का आयात तीन गुना बढ़ जायेगा**

स्वाभाविक रूप से देशभर में इसका कड़ा विरोध हुआ है कि समझौते में जिस तरह से अमेरिका से सभी औद्योगिक और कृषि उत्पादों के आयात पर छूट दी गयी है और कुछ मामलों

(शेष पृष्ठ 3 पर)

## इंदौर जल त्रासदी — जब भारत के "सबसे स्वच्छ शहर" में जीवनदायी जल बना मौत का सबब

दस साल के लंबे इंतजार के बाद जन्मे आंखों के तारे, पांच महीने के नन्हे अव्यान को मां ने ऊपर का दूध आसानी से पचाने के लिए जिस पानी को मिलाया, उसी पानी ने बच्चे की जान ले ली। नये साल का पहला सूरज उगते ही अकेले अव्यान की मां की दर्दभरी चीखें ही नहीं सुनायी दीं, बल्कि भागीरथपुरा के कई घरों के सामने मां-बहनें सफेद कफन से ढके अपने दुलारों की अर्थी पर विलाप कर रही थीं।

**साफ शहर का गंदा पानी**

भागीरथपुरा, मध्य प्रदेश के उस इंदौर की पुरानी और सबसे घनी आबादी वाली मजदूर बस्तियों में से एक है, जो पिछले 8 सालों से भारत के "सबसे स्वच्छ शहर" का तमगा लिये खुशी से फूला नहीं समाता था। नगर निगम के नलों से आ रहे बदबूदार और बदरंग पानी को छानकर और उबालकर पीने के बावजूद बस्ती के लोग लगातार उल्टी-दस्त और कमजोरी का शिकार हो रहे थे। निगम और सरकार के गहरी नींद से जागने तक, अस्पताल सैकड़ों मरीजों से भर चुके थे, जिनमें दर्जनों लोग आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंच गये थे। स्थानीय अखबारों के हिसाब से केवल दस दिनों में मरने वालों की संख्या 17 और बीमार पड़ने वालों की संख्या 2,800 से ज्यादा पहुंच चुकी थी, जबकि उच्च न्यायालय में सरकार केवल 8 मौतें बता रही थी। आंकड़ा तब से लगातार बढ़ ही रहा है और 28वीं मौत 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को दर्ज हुई। 28 दिसंबर से लेकर लेख लिखे जाने तक 30 मौतें हो चुकी थीं और 7 मरीज गंभीर हालत में भर्ती थे।

बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले लोगों पर सबसे ज्यादा कहर टूटा। बाद की जांच में एक भयावह, लेकिन बुनियादी चूक सामने आई। पानी की एक मुख्य पाइपलाइन स्थानीय

(शेष पृष्ठ 6 पर)

## एआईएमएसएस) पश्चिम बंगाल राज्य का राजनीतिक शिक्षण शिविर आयोजित

**घाटशिला (झारखण्ड) :** 27 फरवरी से 1 मार्च तक मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार अध्ययन केन्द्र में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस), पश्चिम बंगाल का राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया।

शिविर में संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड केया डे, महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती, पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सुजाता बनर्जी और सचिव कॉमरेड कल्पना दत्ता मौजूद थीं।

शिक्षण शिविर का संचालन पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और एसयूसीआई (सी) पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य और पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अमिताभ चटर्जी ने किया।

## केन्द्रीय बजट...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक (लगभग 5%) है। लेकिन वे कौन से स्रोत हैं, जहां से सरकार को कमाई की उम्मीद है? कमाई का 24% उधार से होगा। आय का 21% व्यक्तिगत आयकर से होगा। जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों से 15% प्राप्त होगा, जबकि कॉर्पोरेट कर से 18% राजस्व प्राप्त होगा। जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष कर कौन देता है? आम लोग। आबादी के निचले 50% लोग कुल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 64% देते हैं, जबकि शीर्ष 10% केवल 4% का योगदान करते हैं। बाकी गैर-कर राजस्व जैसे शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से लाभांश, ऋण पर ब्याज और रॉयल्टी से है। इसलिए सरकार मेहनतकश जनता से 36% (21+15) कर वसूलती है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा छूट और रियायतें मिलती हैं, जबकि आम लोगों को ठप पड़ी राहत से 'फील गुड' यानी अच्छा महसूस कराया जाता है।

### खर्च का प्लान

अब हम खर्च की बात करते हैं। टैक्स राजस्व का 22% राज्यों को जाता है। और, 20% (14 लाख करोड़ रुपये) तक उधार पर ब्याज के तौर पर खर्च होता है। बाकी 58% सरकार के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। इस साल अनुमानित उधार की रकम 17 लाख करोड़ रुपये होने के साथ, उधार की रकम 214 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 55.6%) को पार कर जाएगी, जबकि पिछले साल उधार की यह रकम 184.56 करोड़ थी। इससे पता चलता है कि राजकोषीय प्रबंधन कितना समझदारी भरा है! अगर 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा प्रति महीने कमाने वालों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, तो सरकार का राजस्व 15,000 करोड़ रुपये बढ़ सकता है। दूसरी ओर, अगर कॉर्पोरेट टैक्स को 22% से थोड़ा बढ़ाकर 25% कर दिया जाए, तो सरकार को लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। तब फिर अमीरों पर ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता और आम लोगों को थोड़ी राहत क्यों नहीं दी जाती, जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई से और कमाई के साधनों की कमी से जूझ रहे हैं?

तभी, "गरीब, शोषित और वंचितों" पर ध्यान देने के दावे में कुछ दम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार का लक्षित श्रोता अलग है। साफ तौर पर कहें तो, वित्तीय संचयन अब एकाधिकारी पूंजीपति घरानों, विदेशी पूंजीनिवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए एक साख बनाये रखने के साधन के तौर पर काम करता है, संप्रभु साख रेटिंग (किसी देश की साख और निवेश जोखिम का स्वतंत्र मूल्यांकन) को सहारा देता है और सरकार की एक काबिल आर्थिक मैनेजर के तौर पर अपनी छवि को चमकाता है।

### 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का दावा

अब "समावेशी विकास" (इन्क्लूसिव ग्रोथ) यानी ऐसा आर्थिक विकास, जो समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीबों और वंचितों, को साथ लेकर चले और उन्हें समान अवसर प्रदान करे, के दावे की बात को लें। वित्तमंत्री ने बताया है कि हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधार-उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। बहुत बढ़िया उपलब्धि! लेकिन क्या यह दावा असलियत से मेल खाता है? इस बहुआयामी गरीबी का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में एक-दूसरे से जुड़ी कमी का आकलन करके सिर्फ कम आय से आगे गरीबी की पहचान करना। यह दिखाता है कि लोग एक ही समय में जरूरी चीजों का कैसे अनुभव करते हैं, जैसे साफ पानी की कमी, खराब पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सही शिक्षा ताकि सिर्फ आमदनी की बजाय गरीबी की ज्यादा पूरी, व्यक्ति-केंद्रित तस्वीर मिल सके। अब, असलियत की बात करते हैं।

कौन नहीं जानता कि खुदरा महंगाई आसमान छू रही है, चाहे रात को दिन दिखाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठु बनने वाले वशेषज्ञों ने जो भी बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़ा जारी किया हो?

आंकड़ों में और हेरफेर न कर पाने के कारण सरकार को हाल ही में यह मानना पड़ा कि खुदरा में बिकने वाले सामानों की महंगाई बढ़ गई है। लेकिन बढ़ोतरी का आंकड़ा आम हिसाब-किताब से 1.33% पर आ गया है। लेकिन खाने की महंगाई 8% बतायी गई है। तब, खाने की महंगाई, असली मजदूरी में भारी गिरावट और बढ़ते कर्ज की वजह से, खासकर ग्रामीण इलाकों में खर्च कम हो रहा है। क्या इससे आम भारतीयों के जीवन स्तर में कोई सुधार दिख रहा है?

सरकार का 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का फैसला ही बताता है कि 60% से ज्यादा दबे-कुचले लोगों के पास खाने की जरूरी चीजें भी नहीं हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के सालों में पांच साल से कम उम्र के 8.8 लाख बच्चों की जान भुखमरी की वजह से चली गई। हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय खाली पेट सोते हैं। हर दिन 7,000 से ज्यादा भारतीय भूख की वजह से मरते हैं। कुपोषण और सेहत की दिक्कतों की वजह से हर दिन 500 से ज्यादा बच्चे मरते हैं। हर दिन 48 किसान आत्महत्या करते हैं।

50% से ज्यादा आबादी को अभी भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। 66% ग्रामीण भारतीयों को कम से कम स्वास्थ्य देखभाल यानी इलाज और जरूरी दवाएं नहीं मिलतीं, 31% लोगों को बेसिक इलाज के लिए 30 किलामीटर से ज्यादा दूर जाना पड़ता है। 1.55 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों में से सिर्फ 3.4% ही भारतीय जन स्वास्थ्य स्तर (आईपीएचएस) के हिसाब से काम कर रहे हैं। 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ 13% (3278) और 8.4% शिशु स्वास्थ्य केंद्र बेसिक स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। लगभग 90 करोड़ लोगों को बहुप्रचारित स्वास्थ्य बीमा स्कीम से पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। अगर बेसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं लोगों, खासकर ग्रामीणों, जो आबादी का लगभग 70% हैं, की पहुंच से दूर हैं, तो इंश्योरेंस कवर का क्या मकसद होगा? क्या जिनके पास नहीं है, वे इलाज के लिए महंगे निजी अस्पताल जा सकते हैं? तब, 25 करोड़ लोग इस बहुआयामी गरीबी से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या यह सिर्फ बकवास नहीं है!

### कृषि और किसान

एक सार्वजनिक भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों की तकलीफ देखकर उनका दिल टूट जाता है। अगर किसानों की भलाई सच में चिंता की बात होती, तो नीतियां सिंचाई, कीमतों में स्थिरता और बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली आदि खेती में काम आने वाली चीजें रियायती दामों में उपलब्ध करवाकर किसानों को सहारा देने पर केंद्रित होतीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा, खेती में बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एकाधिकारी पूंजीपति घरानों को बिना रोक-टोक घुसने में मदद करने के लिए तीन काले खेती कानून कैसे लाए गए थे?

जब किसानों ने दिल्ली से सटे राज्यों के बॉडरों पर एक साल से ज्यादा लंबे अर्से तक ऐतिहासिक विरोध आंदोलन किया था, तो भाजपा सरकार ने दिल्ली से सटे राज्यों के बॉडरों से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को आने से रोकने के लिए हर मुमकिन प्रशासनिक कदम उठाए थे। कड़ाके की ठंड में आंदोलनकारियों पर वॉटर कैनन चलाकर पानी की बौछारें की गई थीं, आंसू गैस के गोले दागे गए थे और लाठीचार्ज किया गया था, जिससे अनगिनत किसान बुरी तरह घायल हो गए थे। शांति से मार्च करने वालों को रोकने के लिए कई लेयर के बैरिकेड लगाये गए थे, बाड़, तार, रेत से भरे कंटेनर और बड़े ट्रक खड़े किये गये थे, सड़कों पर खाई खोदी गई, क्रेन की मदद से बड़े भारी पत्थर डाल दिये गये थे, अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील कर दिये गये थे और कई जगहों पर कर्फ्यू के साथ-साथ धारा 144 भी लगा दी गई थी। किसान आन्दोलन में 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। हालांकि आंदोलन के दबाव में उन तीन काले कानूनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन उन्हें पिछले दरवाजे से वापस लाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने अभी तक सी$_2$+50% के वैज्ञानिक फॉर्मूले के आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी नहीं दी है। जबकि फसल खरीद का बाजार पहले से ही निजी पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है, जो किसानों को उनकी उपज का सही दाम न देकर उन्हें लूट रहे हैं, अब, एक नए बीज एक्ट और दूसरे उपायों के साथ कृषि में काम आने वाली चीजों का पूरा बाजार मुनाफाखोर कृषि कॉर्पोरेटों के लिए खोल दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्र अब प्राइवेट हाथों में है और कृषि से होने वाली आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। इसलिए अब यह बड़ी कंपनियों के लिए खेती का सबसे फायदेमंद शिकारगाह बन गया है।

इस नजरिये से बजट के आंकड़ों को देखें। खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च 25-26 में अनुमानित 1,58,838 करोड़ रुपये से घटाकर 1,51,853 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अगले साल के लिए इसमें सिर्फ लगभग 2% की बढ़ोतरी की गई है, जो मुश्किल से महंगाई को कवर करती है। ग्रामीण विकास के लिए, 2025-26 में 2,65,817 करोड़ रुपये की योजना बनायी गई थी, लेकिन आवंटन 20% कम 2,12,750 करोड़ रुपये था। अगले साल के लिए इसे सिर्फ 3% ज्यादा बढ़ाकर 2,73,108 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, पूंजीवाद के नियम के मुताबिक, जमीन तेजी से कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में ही केंद्रित होती जा रही है। कुछ साल पहले सार्वजनिक हुए एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, जमीन न होने की समस्या बहुत ज्यादा रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में 54.4%, बिहार में 49.3%, पंजाब में 46.3% और तेलंगाना में 42.5%। एनएसएसओ के आंकड़े आगे दिखाते हैं कि शीर्ष 20 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास कुल जमीन का 76 फीसदी हिस्सा था। यह आसानी से माना जा सकता है कि बाद के सालों में ये आंकड़े कई गुना बढ़ गये होंगे।

इसके बाद ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह नये नाम से विबी-ग्राम-जी लाया गया है, जिसके कोष में केन्द्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में बदल दिया गया है। पहले यह अनुपात क्रमशः 90:10 था। इस तरह पैसा देने की एक बड़ी जिम्मेदारी संसाधनों की कमी वाले राज्यों को दे देता है, जबकि रोजगार की कानूनी गारंटी को कमजोर करता है। मनरेगा लंबे समय से ढांचागत और आर्थिक तौर पर खेती से जुड़ा हुआ है। 2014 से यह एक जरूरी जनादेश के तहत काम कर रहा है कि सभी कामों में से कम से कम 60% काम खेती और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े होने चाहिए। खेती के मामले में विबी-ग्रामजी और मनरेगा में जो फर्क है, वह यह नहीं है कि इसमें किस तरह के काम की इजाजत है, बल्कि काम करने का समय है। खेती से जुड़े काम जैसे जल संरक्षण और जमीन का विकास पहले से ही मनरेगा के लिए जरूरी थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जब खेती में मजदूरों की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब रोजगार गारंटी वापस ले ली जाती है। इसकी बजाय नया कानून आखिरकार ग्रामीण मजदूर बाजारों को कानूनी तौर पर फिर से बनाने का काम करता है, जो आय सुरक्षा से ज्यादा मजदूरों की मौजूदगी को प्राथमिकता देता है। जानकारों का कहना है कि विबी-ग्राम-जी अधिनियम ज्यादा केंद्रीकृत है और रोजगार की कानूनी गारंटी नहीं देता है।

इस अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि यह सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये गए इलाकों में ही लागू होगा। इससे मनरेगा के लिए जरूरी सार्वभौमता तुरंत खत्म हो जाती है। गारंटी अब हर जगह स्वतः लागू नहीं होती। 2020-21 में मनरेगा के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये दिये गए थे। लेकिन 2025-26 में यह आवंटन घटकर 86,000 करोड़ रुपये रह गया। अब, विबी-ग्राम-जी को 95,692 करोड़ रुपये मिले हैं, जो गांव के परेशान बेरोजगारों को गुजारा करने लायक मजदूरी देने के लिए हर हिसाब से बहुत कम है।

भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों का दूसरे राज्यों में असंगठित क्षेत्र में ठेके के तौर पर मामूली कमाई के लिए प्रवासी मजदूर में रूपान्तरण खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। अब खबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कृषि बाजार खुलने से भारतीय किसान लगभग बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह सरकार किसानों के लिए घड़याली आंसू बहा रही है।

### मजदूर भी हैं उतने ही परेशान

इसी तरह, मजदूरों का क्या हाल है? पक्की-स्थायी नौकरी तो बीते जमाने की बात हो गई है।

अब तो बहुत कम तनख्वाह पर अनुबंध-ठेके पर कच्ची, कैजुअल और नियत अवधि की नौकरी का जमाना है। सरकार भी स्थायी प्रकृति की नौकरियों के लिए भी अनुबंध के आधार पर मजदूर-कर्मचारी रख रही है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार के लोकसभा को दिये गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वित्त वर्षों में (वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक) भारत में 2.04 लाख (2,04,268) से ज्यादा निजी कंपनियां बंद हो गईं इसलिए बड़ी संख्या में मजदूर अपनी नौकरी गवां चुके हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में विनिवेश के कारण नियमित कर्मचारियों की संख्या में पांच साल में 1.08 लाख की कमी आयी (2019-20 में 9.2 लाख से 2023-24 में 8.12 लाख तक)। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 2021-22 और 2022-23 के लिए जारी असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के ताजा सालाना सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले सात सालों में लगभग आधे भारतीय राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह देखने में आया कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत नौकरियां गईं।

इसके अलावा, हाल ही में पारित हुए चार काले लेबर कोड, मजदूरों के पास अब तक जो भी थोड़ी-बहुत सुरक्षा थी, उसे भी खत्म कर देंगे और मालिकों को जो चाहे करने की खुली छूट दे देंगे-जब चाहे मजदूरों को काम पर रखना और निकालना, मौजूदा श्रम सुरक्षा छीनना और उनके हड़ताल करने के अधिकार का उल्लंघन करना। दूसरी ओर, ये कोड 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी कारोबार करने में सुगमता की आड़ में मुनाफाखोर कॉर्पोरेट पूंजीपति घरानों के लिए पलक-पांवड़े बिछा देते हैं।

### बढ़ रही है बेरोजगारी

बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर हाल के सालों में 6%-8% के बीच ऊपर-नीचे होती बतायी गई है (पीएलएफएस)। यह फिर से एक सावधानी से बुना गया दिखावा है। बड़ा मुद्दा अनौपचारिक रोजगार है, जहां लगभग 90% मजदूर कम मजदूरी वाली और असुरक्षित नौकरियों में लगे हुए हैं। युवाओं में बेरोजगारी अभी भी ज्यादा है, खासकर पढ़े-लिखे युवाओं में, 18% से ज्यादा शहरी युवा बेरोजगार हैं (PLFS 2023)। भारत को खेती में भी बड़े पैमाने पर छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जहां बहुत ज्यादा मजदूर खेती के सीमित उत्पादन में हिस्सा लेते हैं, जिससे गांवों में मजदूरी कम रहती है और गरीबी बनी रहती है।

श्रम बाजार में कम रोजगार और अनौपचारिक काम हावी हैं, इनफॉर्मल

(शेष पृष्ठ 7 पर)

# धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री की भड़काऊ और नफरती बयानबाजी

कष्टों से त्रस्त मानवता की समस्याओं को भले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक जहर उगलकर लोगों को बांटने, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ाने और उन्माद भड़काकर व दुश्मनी पैदा करके जनता के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के अथक प्रयासों में तेजी बरकरार रहेगी। हाल के दिनों में, सत्ताधारी भाजपा नेताओं के बीच इस मुद्दे पर होड़-सी मची हुई है। कौन दूसरों से ज्यादा बेशर्म और बेहतर नफरत फैलाने वाला प्रचारक बन सकता है और इस तरह उन शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों की कृपादृष्टि प्राप्त कर सकता है, जो करोड़ों शोषित लोगों की संघर्षशील एकता में दरार पैदा करके किसी तरह अपने मरणासन्न अस्तित्व को बचाये हुए हैं।

याद रखें, अनुराग ठाकुर, जो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ने खुलेआम धार्मिक अल्पसंख्यकों को 'गोली मारो ...' का आह्वान किया था। अब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शायद घोर सांप्रदायिक हिंदुत्व के कट्टर चेहरे के रूप में अपनी साख साबित करने के लिए उन सबसे आगे निकल गए हैं। हाल ही में, उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का खुला आह्वान किया है और नागरिकों से उन्हें जमीन, परिवहन और आजीविका देने से इनकार करने का आग्रह किया है ताकि उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। वे इस हद तक चले गए कि 7 फरवरी को असम भाजपा इकाई के आधिकारिक 'X' हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें वे प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर करीब से (पॉइंट-ब्लैंक रेंज) गोली चलाते हुए दिखायी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा, वे लोगों का ध्यान उनके तेजी से गिरते जीवन स्तर, बढ़ती बदहाली और कंगाली के असली कारणों से भटकाने के लिए और कर भी क्या सकते हैं?

स्मरण रहे कि असम में बांग्ला भाषा भाषी मुसलमान राज्य के सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर रहने वाले समुदायों में से हैं। आरएसएस-भाजपा नेताओं द्वारा उनको पीढ़ियों से वहां रहने के बावजूद अक्सर 'बाहरी' या 'अवैध घुसपैठियों' के रूप में चित्रित किया जाता है–एक ऐसा नैरेटिव, जिसने घरों से बेदखली, मताधिकार से वंचित करने और निशाना बनाकर प्रशासनिक कार्रवाई करने को बढ़ावा दिया है। अत: उन्हें अवैध 'विदेशी' करार देना और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है।

मुख्यमंत्री और आरएसएस- भाजपा गठबंधन द्वारा असम के धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित गरीब वैध भारतीय नागरिकों के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे जहरीले नफरत अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (सी) की असम राज्य सचिव कॉमरेड चंद्रलेखा दास ने 03-02-26 को जारी एक बयान में कहा कि ऊपरी असम में धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर हालिया हमला राज्य में व्याप्त भयावह सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। ये मेहनतकश अत्यंत गरीब और प्रामाणिक भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश किसान हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन गरीब मेहनतकश लोगों पर हमला न केवल गैरकानूनी है, बल्कि अमानवीय भी है। यह बेरोक-टोक चलाया जा रहा नफरती अभियान न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। कहना न होगा कि एक समुदाय के गरीब कभी भी दूसरे समुदाय के गरीबों के अधिकारों को नहीं छीनते हैं, बल्कि देश पर बोझ की तरह लदे शोषक पूंजीवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने से उनकी संघर्षशील एकता और मजबूत होती है। संयुक्त आंदोलन के सांस्कृतिक परिवेश में सभी पैदा किये गए विभाजन, कड़वाहट, आपसी नफरत और ऐसी अन्य दुर्भावनापूर्ण मानसिकताएं समाप्त हो जाएंगी।

एसयूसीआई (सी) ने राज्य के लोगों से उन गरीबों, मेहनतकशों और निर्दोष लोगों के साथ खड़े होने और शासक पूंजीपति वर्ग के ताबेदारों के इस उद्देश्य प्रेरित अभियान का शिकार न होने का आह्वान किया है।

साथ ही उन्होंने साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों की साजिशों को विफल करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखना सुनिश्चित करने और आपसी भाईचारे व सौहार्द को मजबूत बनाने की अपील भी की है।

## भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

में शून्य शुल्क की बात कही गयी है, उससे भारतीय किसान भारी नुकसान की चपेट में आ जायेंगे। मध्यम और लघु उद्योग भी अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ में बह जायेंगे। इस समझौते से शायद कुछ ज्यादा भारतीय उत्पादों का निर्यात करना संभव हो और इससे बड़ी भारतीय कंपनियों का व्यवसाय भी कुछ फल-फूल जाये, लेकिन इससे देश के बहुसंख्यक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

इस समझौते में वास्तव में किन-किन वस्तुओं का आयात-निर्यात होगा, यह न तो अमेरिका ने और न ही भारत ने अपने देश की जनता के सामने स्पष्ट किया है। ऐसा क्यों नहीं किया? यह गोपनीयता क्यों? सरकार जनता से क्या छिपाना चाहती है, भाजपा नेताओं को इसका साफ जवाब देना होगा। आयात-निर्यात के जो आंकड़े घोषित किये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि अमेरिका से भारत का आयात तीन गुना बढ़ जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु-मंझोले उद्योगों, स्टार्ट-अप्स और मछुआरों के लिए नये अवसर पैदा करेगा। भारत ने अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों के आयात को मंजूरी दे दी है। यह कौन नहीं जानता कि उच्चतम तकनीक के इस्तेमाल के कारण अमेरिकी उत्पादों की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है? अगर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बिना किसी शुल्क या नाममात्र के शुल्क पर भारतीय बाजार में आते हैं, तो भारत के उद्यमी, लघु-मंझोले उद्योग और स्टार्ट-अप इससे कैसे लाभान्वित होंगे? दरअसल, इस असमान प्रतिस्पर्धा में ये संस्थाएं टिक ही नहीं पायेंगी। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। अमेरिकी ब्लेड निर्माता कंपनी 'जिलेट' के भारत में व्यापार शुरू करने के बाद भारतीय ब्लेड निर्माता कंपनियों का क्या हश्र हुआ? लगभग सभी को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। अन्य छोटे और मध्यम उद्योगों का भी यही हश्र होगा।

भारत, अमेरिका के अनगिनत खाद्य पदार्थों व कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क या तो घटा देगा या पूरी तरह से हटा देगा। आयात सूची में पशु आहार के साथ-साथ सोयाबीन तेल, बादाम, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सेब, कपास, शराब और 'अतिरिक्त' उत्पादों का जिक्र किया गया है। ये अतिरिक्त उत्पाद क्या-क्या हैं, इसे संयुक्त बयान में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि और भी कई उत्पादों का आयात किया जायेगा, जिन्हें जन आक्रोश के डर से दोनों देशों के नेता अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी विदेशी समझौते में कृषि क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए इस तरह से नहीं खोला गया था।

### आयात में बढ़ोतरी के दुष्प्रभाव

अमेरिका से पशु आहार और सोयाबीन तेल के आयात का क्या नतीजा होगा? वर्तमान में, देश में पोल्ट्री, मछली पालन और पशुपालन उद्योग में सोयाबीन, बिनौलों, मूंगफली या चोकर से तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, उसका इस्तेमाल पशु आहार के तौर पर किया जाता है। समझौते के अनुसार, अमेरिका में मक्के से इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के उप-उत्पाद डीडीजी (ड्रायड डिस्टिलर्स ग्रेन्स) और लाल ज्वार का आयात भारतीय सोयाबीन किसानों को भारी नुकसान पहुंचायेगा। क्योंकि किसान अभी जिस कीमत और पोषण मूल्य वाली डी-ऑयल्ड खली खरीदते हैं, उसकी तुलना में डीडीजी काफी सस्ती है। कपास और सेब उत्पादक किसानों का भी यही हश्र होगा। अमेरिकी कपास की गुणवत्ता बहुत बेहतर होने के कारण भारतीय कपास उत्पादक किसान पूरी तरह बर्बादी की कगार पहुंच जायेंगे। दूसरी ओर, अमेरिका ने भारतीय वस्त्रों पर 18 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। साथ ही उसने यह शर्त रखी है कि केवल अमेरिकी कपास से निर्मित वस्त्रों को ही शुल्क में छूट मिलेगी।

यूरोप और अमेरिका से समझौते के बाद अगर भारतीय बाजार में विदेशी सेबों का धड़ल्ले से आना जारी रहा, तो कश्मीर समेत भारत के लाखों सेब उत्पादक किसान जबरदस्त नुकसान की चपेट में आ जायेंगे। कश्मीर के सेब उत्पादक किसानों ने पहले ही बड़े नुकसान की आशंका जताते हुए सरकार से विदेशी सेबों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग की है। अमेरिका के कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस ने दावा किया है कि व्यापार समझौते के नतीजतन अमेरिकी कृषि उत्पाद और ज्यादा मात्रा में भारतीय बाजार में आयेंगे, जिससे अमेरिका के गांवों में डॉलर की आमद होगी। याद रखना होगा कि कृषि उत्पादों के इस आयात-निर्यात में दोनों देशों के आम किसानों का कोई हित नहीं है। अमेरिका में कृषि मुख्य रूप से 'बिग-फार्मिंग' यानी बड़ी पूंजी द्वारा नियंत्रित है। यह उच्च तकनीक और भारी सरकारी सब्सिडी पर निर्भरशील है। इसी तरह, भारत की कृषि में छोटे और मंझोले किसानों की भूमिका तो है, लेकिन कृषि उत्पादों के निर्यात व्यापार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमेशा ही अभावों में रहने की वजह से उन्हें अपने उत्पाद कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। औद्योगिक उत्पादों की तरह ही, कृषि उत्पादों का व्यापार भी अब पूरी तरह से बड़ी पूंजी के कब्जे में है। विदेशी व्यापार की बात तो छोड़ ही दीजिए।

### विदेशों में निर्यात का लाभ उठाएंगे बड़ी पूंजी के मालिक

मुख्य रूप से अदानी और अंबानी समूह ही भारत के विदेशी कृषि-व्यापार में आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन), लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचागत सहायता के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। जिस तरह अदानी समूह बंदरगाहों का संचालन करता है, वैसे ही इस समूह ने बड़े आधुनिक गोदाम बना लिये हैं, जो खाद्यान्नों के दीर्घकालिक भंडारण और त्वरित आयात में मदद करते हैं। अदानी विल्मर अपने ब्रांड के जरिये विश्व बाजार से खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करती है। दूसरी ओर रिलायंस रिटेल सीधे किसानों से उत्पाद संग्रह करती है और खुदरा बिक्री को नियंत्रित करती है, जिससे विदेशी व्यापार में उत्पादों की आपूर्ति बढ़ती है। रिलायंस फ्रेश या रिलायंस रिटेल के जरिये अंबानी समूह आयातित और घरेलू उत्पादों की एक विशाल आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है। इसलिए यह समझने में दिक्कत नहीं है कि भारत से जो भी कृषि उत्पाद विदेशों में निर्यात क्यों न हो, उसका लाभ आम किसानों को मिलने वाला नहीं है। ये कंपनियां किसानों से कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर खरीदकर विदेशी बाजारों में महंगे दामों पर बेचेंगी। देश में भी इसके ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के किसान जिस प्याज को दो रुपये प्रति किलो के भाव से बड़े प्याज व्यापारियों को बेचने को मजबूर होते हैं, कुछ ही महीनों में देश की जनता उसी प्याज को 50-60-80 रुपये और कभी-कभी तो 100 रुपये प्रति किलो के दाम पर खरीदने को मजबूर होती है। कृषि हो या उद्योग, किसी भी उत्पाद का आयात-निर्यात अरबपतियों द्वारा नियंत्रित विदेशी व्यापार सिंडिकेट ही करेंगे।

नतीजतन, भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों से भर जायेगा। अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार, शुरू में भले ही भारतीय खरीदारों को कुछ समय के लिए सस्ते उत्पाद खरीदने का मौका मिल जाये, लेकिन जैसे ही भारतीय उत्पादक असमान प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार छोड़ने को मजबूर होंगे, अमेरिकी उत्पादों की कीमतें बढ़ जायेंगी। इसके अलावा, किसी उत्पाद के सस्ते आयात का मतलब यह नहीं है कि देश के आम उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिलेगा ही। इसका जीता जागता उदाहरण रूस से मिलने वाला सस्ता तेल है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद, रूस अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों की तुलना में काफी सस्ते दामों पर भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हो गया। भारतीय कंपनियों ने उस तेल का भारी मात्रा में आयात किया और बेतहाशा मुनाफा कमाया। लेकिन इसका कोई फायदा देश की आम जनता को नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से, अगर विदेश का कोई उत्पाद बिना शुल्क के या अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर भी आयात किया जाता है, तो उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। सारा का सारा मुनाफा बड़ी पूंजी द्वारा नियंत्रित सिंडिकेटों की झोली में चला जायेगा।

भारत से अमेरिका को इस्पात, तांबा, गाड़ी के पुर्जे, वस्त्र, चमड़ा, जूते और रत्न-आभूषण जैसे लगभग 9,000 करोड़ रुपये के उत्पाद निर्यात किये जायेंगे। इन क्षेत्रों में उत्पादक और निर्यातक बड़ी कंपनियों की ओर से सरकार पर समझौता शीघ्र पूरा करने का दबाव था।

### अमेरिका और भारत के बड़े पूंजीपतियों के ही दबाव में हुआ समझौता

हालांकि इस असमान समझौते से देश के आम किसान-मजदूरों और आम लोगों के हित खतरे में पड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि इससे दोनों देशों की बड़ी पूंजी के हित सधेंगे, इसलिए इस समझौते के पीछे अमेरिकी अरबपतियों के साथ-साथ भारतीय अरबपतियों का भी दबाव था। अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापार घाटे को कम करना उसके लिए बेहद जरूरी था। वहीं, यह सच है कि निर्यात के क्षेत्र में भारत की अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत को अमेरिकी शर्तें मानने को मजबूर किया है, लेकिन निर्यात व्यापार को निरंतर बनाए रखने के लिए भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों ने भारत सरकार को जरूरत पड़ने पर जनहित की बलि देने को मजबूर किया है।

ऐसा नहीं है कि भारत केवल कृषि और औद्योगिक उत्पादों का ही आयात करेगा। वह बड़ी मात्रा में तेल, गैस और आधुनिक हथियार भी खरीदेगा। बहुतों को याद होगा कि ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे। मोदी को बगल में बिठाकर ट्रंप ने घोषणा की थी कि 2025 से अमेरिका भारत को हथियारों की बिक्री बढ़ाएगा। भारत अमेरिका से एफ-35 लड़ाकू

(शेष पृष्ठ 7 पर)

## एआईएसईसी ने जन संसद की दी जानकारी

**बरनाला ( पंजाब ):** 13 फरवरी को बरनाला जिले के मीरी पीरी कॉलेज, भदौर में मशहूर साहित्यकार देविंदर सत्यार्थी की याद में हुए एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी), पंजाब चैप्टर के सचिव अमरिंदरपाल सिंह ने वैकल्पिक शिक्षा नीति के लिए आयोजित सफल ऐतिहासिक जन संसद और भविष्य के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

## बेरोजगारी के खिलाफ एसआइडीवाईओ ने किया विरोध प्रदर्शन

**रोहतक ( हरियाणा ) :** ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाईजेशन (एआईडीवाईओ) ने पदों को जानबूझकर खाली रखने, सभी अभ्यर्थियों को अयोग्य बताने, बढ़ती बेरोजगारी व युवाओं की विभिन्न समस्याओं के खिलाफ 22 फरवरी को यहां मानसरोवर पार्क से उपायुक्त, रोहतक के कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन की मार्फत देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड बलवान सिंह ने कहा कि बड़े ही शातिराना ढंग से अस्सिटेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर टीचर व अन्य भर्तियों में भारी संख्या में पदों को खाली छोड़ा गया है और प्रदेश के नौजवानों पर अयोग्य का ठप्पा लगाया जा रहा है। यह बेहद ही निंदनीय और चिंताजनक है।

एआईडीवाईओ के जिला संयोजक कॉमरेड हरीश सैनी ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और भर्तियों में हो रही अनियमितताओं से युवा वर्ग गहरे असंतोष में है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। नए रोजगार सृजन करने की बजाय पदों को खत्म किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, त्वरित और नि:शुल्क बनाया जाए। भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचने की वजह से अनेक युवाओं की फॉर्म भरने की उम्र निकल जाती है।

एआईडीवाईओ केंद्र व राज्य सरकार से मांग करता है कि सरकार युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए खाली पदों को शीघ्र भरे, रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, पदों को खाली न छोड़ा जाए, उम्र की सीमा जैसी तमाम बाधाएं दूर करके सबको रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए और नशाखोरी व अश्लीलता पर रोक लगाई जाए।

सभा को एडवोकेट अजय, संदीप, वजीर, बृजमोहन आदि ने भी संबोधित किया।

## एआईडीएसओ की बैठक संपन्न

**घाटशिला ( झारखण्ड ) :** ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन, झारखंड राज्य के संगठनकर्ताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक केंद्रीय परिषद अध्यक्ष कॉमरेड सौरभ घोष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष कॉमरेड समसुल आलम, कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड विश्वजीत राय, कॉमरेड निरुपमा बेहरा, प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड समर महतो और प्रदेश सचिव कॉमरेड सोहन महतो की उपस्थिति में 14 फरवरी को घाटशिला स्थित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार अध्ययन केंद्र में संपन्न हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई।

### भारत-अमेरिका व्यापार समझौते एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ
## जीत तक देशव्यापी संयुक्त संघर्ष का एसकेएम का एलान



कुरुक्षेत्र : संयुक्त किसान मोर्चे की अखिल भारतीय बैठक में अपने सुझाव रखते हुए कॉमरेड राजेन्द्र सिंह

**कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ):** भारत-अमेरिका व्यापार समझौते एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ जीत तक देशव्यापी संयुक्त संघर्ष का एसकेएम ने एलान किया है। 24 फरवरी को स्थानीय जाट धर्मशाला में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की अखिल भारतीय बैठक में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) की तरफ से संगठन के नेता कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने विचार रखे। 9 मार्च को जंतर-मंतर पर मजदूर-किसान संसद का कार्यक्रम है। 10 मार्च से 13 अप्रैल (जलियांवाला बाग दिवस) तक देशभर में महापंचायतें होंगी, जिनकी शुरुआत बरनाला (पंजाब) से 23 मार्च को देशव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाकर होगी।

## स्मार्ट मीटर लगाये जाने, बच्चियों व महिलाओं पर बढ़ते जुल्मों और शिक्षा-स्वास्थ्य-बिजली-पानी के निजीकरण का विरोध

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के आह्वान पर 12 फरवरी से 17 फरवरी राज्यव्यापी विरोध सप्ताह के तहत केंद्र व राज्य सरकार की प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जाने, महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध व शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तथा पानी के निजीकरण की नीति के खिलाफ गुना अशोकनगर, इंदौर, देवास, ग्वालियर, भोपाल, सागर आदि में विरोध प्रदर्शन किये गये।

इस मौके पर ग्वालियर में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की ग्वालियर जिला सचिव कॉमरेड रचना अग्रवाल, भोपाल में पार्टी जिला सचिव कॉमरेड मुदित भटनागर, अशोकनगर में जिला सचिव कॉमरेड सचिन जैन, गुना में जिला सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव, इंदौर में जिला सचिव कॉमरेड अर्शी खान और सागर में पार्टी राज्य कार्यालय सचिव कॉमरेड राम अवतार शर्मा ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार एक के बाद एक घोर जनविरोधी नीतियां लागू कर रही हैं, जिसके चलते आम गरीब मेहनतकश लोगों का जीवनयापन मुश्किल हो गया है। बाजार में काम-धंधों का न चलना, बेतहाशा बेरोजगारी और भयंकर मंहगाई के कारण आम लोग पहले से ही बेहाल हैं। बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवा से मुनाफा कमाने के उद्देश्य से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना आम लोगों की सरासर लूट है। इससे जनता को डर सता रहा है। बिजली वितरण कम्पनी के कर्मचारी




बच्चों व महिलाओं के गायब होने की संख्या बढ़ रही है। यही है 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' नारे की हकीकत।

फसलों का उचित दाम व बर्बाद फसलों का समुचित बीमा क्लेम और मुआवजा नहीं मिलने से प्रदेश में किसान-मजदूर बदहाली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मजदूर-विरोधी चार लेबर कोड थोपकर श्रम अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

सरकारी अस्पतालों को पीपीपी माडल पर निजी हाथों में देने और जिला चिकित्सालय में सभी बंद जांच केंद्र शुरू कर पर्याप्त स्टाफ व डाक्टरों की भर्ती न कर गरीबों से उनका ये आसरा छीनने का निंदनीय काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के







गाली-गलौज जैसी अभद्रता करके व झूठे केस में फंसाने या फिर विद्युत आपूर्ति काटने की धमकी देकर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर उतारू हैं। यह पूरी तरह गलत है।

शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को सांदीपनी स्कूलों में मर्ज करके बंद करने की सरकारी नीति भी आम गरीब छात्रों, विशेषकर छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर विवश कर देगी। 15 किलोमीटर के दायरे के तमाम स्कूलों को बंद कर बाद में इन सांदीपनी स्कूलों को भी ठेके पर देने की योजना है।

सरकार द्वारा चौक-चौराहों पर शराबखाने खोले जा रहे हैं। गली-गली में शराब पहुंचाने की तैयारी है। छात्र-नौजवानों को शिक्षा और रोजगार से महरूम किया जा रहा है। उन्हें आदर्शहीन बनाकर जानवर में तब्दील किया जा रहा है। नतीजतन, अभी प्रदेश में लगातार महिलाओं व बच्चियों पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को नशा, अश्लीलता और अपसंस्कृति का शिकार बनाकर उन्हें जघन्य अपराध की ओर धकेला जा रहा है। प्रदेश में मासूम

लोगों को साफ पानी भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 32 मौतें सरकार की घोर आपराधिक लापरवाही है। इस घटना के बाद कई मिनरल वाटर कम्पनियां सक्रिय हुई हैं और जनता भी डर के कारण रोज कैम्पर खरीदकर पानी पीने को मजबूर हुई है। कहीं न कहीं ये पेयजल के निजीकरण की साजिश भी है।

सरकार पर्यावरण को नष्ट कर रही है। आदिवासी वनवासियों के हितों को ताक पर रखकर सरकार खनिज संसाधनों से मुनाफा कमाने के उद्देश्य से जल-जंगल-जमीन को बड़े कारपोरेटों के हवाले कर रही है। यह दिखाता है कि सरकार की हर नीति और योजना के पीछे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के जरिये कंपनियों का हित साधना ही मकसद है।

ऐसे में, जनांदोलन ही मेहनतकशों के लिए बचने का एकमात्र रास्ता है। हम तमाम मेहनतकशों से इन मुद्दों पर एकजुट होने की अपील करते हैं।

# महान क्रान्तिकारी योद्धा चन्द्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस पर देशभर में स्मृति सभाएं आयोजित

**प्रयागराज ( उत्तर प्रदेश ) :** काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति, प्रयागराज के तत्वावधान में आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को अंजुमन रूहे अदब सभागार, प्रयागराज में काकोरी एक्शन के सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें शहादत दिवस पर एक स्मृति सभा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी चिंतक श्री नरेश सहगल ने की। मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात लेखक श्री सुधीर विद्यार्थी उपस्थित रहे। वक्ताओं में श्री सुरेन्द्र राही, काकोरी एक्शन कमेटी के श्री विकास मौर्य एवं श्री सईद सिद्दीकी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री विजय शंकर सिंह द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्रांतिकारी गीतों की ओजपूर्ण प्रस्तुति श्री विनय त्रिपाठी द्वारा की गई, जिससे सभागार में राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी माहौल में विकास मौर्य ने कहा कि काकोरी एक्शन के शहीदों के संघर्ष, त्याग और उनकी साझी विरासत की सोच को आज जन-जन तक पहुंचाना समय की मांग है। वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. राय ने शहीदों की विरासत की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सुरेन्द्र राही ने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, उसके उद्देश्यों एवं इतिहास पर विस्तार से अपने विचार रखे।

मुख्य वक्ता सुधीर विद्यार्थी ने अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद के जीवन, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता तथा शोषणमुक्त समाज के निर्माण में क्रांतिकारियों के संकल्प को रेखांकित किया। उन्होंने वर्तमान दौर में उनकी विरासत से प्रेरणा लेते हुए संघर्ष को जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने गोरखपुर में बेटे राम प्रसाद बिस्मिल की अर्थी के सामने वक्तव्य देते हुए कहा था कि मेरा बेटा बिस्मिल देश के लिए कुर्बान हो गया, किंतु देश के काम के लिए मेरा दूसरा बेटा भी है। मैं चाहूंगी कि दूसरा बेटा भी अपने भाई की तरह देश के काम आए।

उन्होंने देश के क्रांतियारियों के इतिहास को विकृत करने वालों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि क्रांतिकारियों की धारा और गांधीवादी धारा को एक साथ बताना गलत है। इसी तरह सावरकर को क्रांतिकारियों के साथ खड़ा करना पूरे इतिहास को विकृत करना है। उन्होंने आजादी आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के शहीदों को याद करते हुए देश की साझी विरासत को बचाने और इतिहास को विकृत करनेवालों के खिलाफ मुखर होने की अपील की।

उन्होंने काकोरी के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की मां द्वारा झेली गई आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए क्रांतिकारियों और उनके परिजनों के त्याग को याद किया।

अध्यक्षीय संबोधन में वयोवृद्ध समाजवादी चिंतक नरेश सहगल ने इलाहाबाद की साझी विरासत को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे बचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे आने की जरूरत है।

अंत में सभी उपस्थितजनों ने क्रांतिकारियों के आदर्शों पर चलने और उनके सपनों के भारत के निर्माण हेतु संकल्प व्यक्त किया।

**जौनपुर ( उत्तर प्रदेश ) :** आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी व अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें शहादत दिवस के अवसर पर काकोरी-एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति ने 27 फरवरी को यहां नगरपालिका परिषद टाउन हॉल मैदान में श्रद्धांजलि सभा की, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभा में राष्ट्रवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जी.एल. निषाद ने की। संचालन प्रमोद कुमार शुक्ल ने किया। श्रद्धांजलि सभा को अपूर्व दूबे, इन्दुकुमार शुक्ल, मोहित प्रजापति, दिलीप कुमार खरवार, संतोष कुमार प्रजापति, पूनम प्रजापति इत्यादि ने सम्बोधित किया। अंजली सरोज व जिमी गुप्ता ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम की शुरुआत महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई और समापन जोरदार नारों के साथ हुआ।

लंभुआ, सुल्तानपुर में महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद शहादत दिवस एआईडीवाईओ के तत्वावधान में सम्मानपूर्वक मनाया गया।

**रांची ( झारखंड ) :** छात्र संगठन एआईडीएसओ ने 27 फरवरी को जैन कॉलेज, धुर्वा, रांची में शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया।

**अहमदाबाद ( गुजरात ) :** एआईडीएसओ और एआईडीवाईओ ने मिलकर 27 फरवरी को यहां हिम्मतलाल पार्क गार्डन में शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस मनाया।

**पिलानी ( राजस्थान ) :** महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर 27 फरवरी को यहां ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) ने महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और सभी नौजवानों को रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया।

**भिवानी ( हरियाणा ):** आजादी आंदोलन की समझौताहीन संघर्ष की धारा के महान क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस के अवसर पर 27 फरवरी 2026 को स्थानीय नेहरू पार्क में एआईडीवाईओ तथा शहीद एवं महापुरुष यादगार कमेटी, भिवानी ने मिलकर स्मृति सभा की। इसमें युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। सभी ने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पितकर श्रद्धांजलि दी।

एआईडीवाईओ के जिला संयोजक कॉमरेड संदीप मेहरा, राजेश और जिला अध्यक्ष कॉमरेड धर्मवीर सिंह ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला।

सभा के मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड रामफल थे। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने देश को केवल अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के शोषण-जुल्म से मुक्त कराने का सपना देखा था। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के जरिये देश को राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन क्रांतिकारियों, शहीदों और आम लोगों के संघर्षों व कुर्बानियों का सारा फल देश के शोषक पूंजीपतियों ने हड़प लिया। शोषण से मुक्ति का क्रांतिकारियों का सपना पूरा नहीं हुआ। वह सपना आज भी अधूरा है। आजादी के इतने साल बाद भी मजदूर-किसानों सहित मेहनतकश आम लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी गंभीर समस्याओं से त्रस्त हैं। अश्लीलता और नशाखोरी परोसकर बच्चे बिगाड़े जा रहे हैं। साम्प्रदायिकता, जातपात और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर मेहनतकशों की एकता और भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। इसलिए आज क्रांतिकारियों के जीवन-संघर्ष से सीख लेकर छात्र-युवाओं और किसान-मजदूरों को संगठित होकर वर्तमान हर तरह के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी। इस जिम्मेदारी को निभाने लायक बनने के लिए महनतकशों को सही विचारधारा और उन्नत चरित्र हासिल करना होगा।

सभा की अध्यक्षता शहीद एवं महापुरुष यादगार कमेटी के जिला संयोजक कॉमरेड राजकुमार बासिया ने की। चन्द्रशेखर आजाद शहीदी दिवस पर तोशाम में भी शहीद-महापुरुष यादगार कमेटी और रिटायर्ड फौजियों के संगठन ने स्मृति सभा की, जिसे मुख्य रूप से कॉमरेड रोहतास सैनी ने संबोधित किया।

**गुरुग्राम ( हरियाणा ) :** शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस पर 27 फरवरी को गुरुग्राम के प्रकाश पुरी चौक पर एआईडीवाईओ

व एआईयूटीयूसी द्वारा यादगार सभा की गयी। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं तथा भवन निर्माण श्रमिकों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत में उपस्थित साथियों ने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सभा को एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड श्रवण कुमार गुप्ता और कॉमरेड निरंजन लाल, एआईडीवाईओ के राज्य संयोजक कॉमरेड बलवान सिंह, जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड वजीर सिंह, कॉमरेड पिंटू कुमार, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव कॉमरेड हेमराज

तथा श्रमिक मुकेश ने संबोधित किया।

**सोनीपत ( हरियाणा ) :** 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर अशोक विहार कार्यालय में सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता एआईडीवाईओ के अध्यक्ष कॉमरेड देवेंद्र सिंह ने की। संचालन कॉमरेड भारत ने किया। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी थे। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद के क्रान्तिकारी आन्दोलन में उनकी भूमिका, योगदान, महान चारित्रिक गुणों और काबिलियत का जिक्र करते हुए जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला।

एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड देवेंद्र सिंह, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने भी शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धासुमन अर्पित किये। इस अवसर पर एआईडीएसओ के कॉमरेड अमित कुमार व ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव कॉमरेड जयकरण दहिया ने क्रांतिकारी गाने सुनाये।

**कैथल ( हरियाणा ) :** नौजवानों के संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) व केंद्रीय ट्रेड यूनियन ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की ओर से शहीद चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान पर 27 फरवरी को यहां हनुमान वाटिका में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड राजकुमार सारसा ने की व मंच संचालन एआईडीवाईओ के जिला प्रधान कॉमरेड नरेश कुमार ने किया। सभा में सबसे पहले शहीद चन्द्रशेखर आजाद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये। एआईयूटीयूसी की ओर से कॉमरेड कमल कुमार व ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य कमेटी उपप्रधान कॉमरेड बाबूराम ने भी जनसभा को संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश के आजादी आंदोलन में बहुत से नौजवानों ने एक से बढ़कर एक बेजोड़ कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं में एक चमकते हुए सितारे की तरह थे गैर-समझौतावादी धारा के महान योद्धा चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे शहीद हो गए थे। भारत में समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य को लेकर शहीद भगत सिंह की पहल पर क्रांतिकारियों ने अपने संगठन का नाम एचआरए से बदल कर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (एचएसआरए) रखा लिया था। चंद्रशेखर आजाद की अनुपस्थिति में उन्हें संगठन का सर्वोच्च नेता चुना गया था।

**रोहतक ( हरियाणा ) :** 27 फरवरी को चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में भी एआईडीएसओ ने सभा करके चन्द्रशेखर आजाद को याद किया। छात्र नेता कॉमरेड उमेश मौर्य ने सभा को संबोधित किया।

PRGI Regn. No. 43022



## इंदौर जल त्रासदी...

( पृष्ठ 1 का शेष )

पुलिस चौकी से सटे पार्क के एक ऐसे सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही थी, जिसमें न तो जरूरी सेप्टिक टैंक था और न ही सीवर लाइन से कोई कनेक्शन। मल-मूत्र पार्क में एक खुले गड्ढे में जमा हो रहा था। जर्जर पाइपलाइन में रिसाव के चलते यह गंदगी पीने के पानी में मिल गई, जो बस्ती के हजारों घरों में सप्लाई हो रहा था।

### किडनी व लिवर तक खराब कर देने वाले खतरनाक बैक्टीरिया

प्रयोगशाला जांच में पाया गया कि भागीरथपुरा में सप्लाई किया गया पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं था। इसमें फीकल कोलिफॉर्म, ई-कोलाई, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, विब्रियो, क्लेब्सिएला और सिट्रोबैक्टर जैसे जानलेवा बैक्टीरिया पाये गए, जिससे पानी में मानव मल-मूत्र मिले होना साबित हो गया। भागीरथपुरा में पानी की कई लाइनें भी टूटी पायी गईं। दशकों पहले अव्यवस्थित रूप से बिछायी गयी पानी की पाइप लाइनें और सीवर लाइनें खतरनाक रूप से पास-पास थीं।

चूंकि इस इलाके में दिन में केवल एक घंटे पानी की सप्लाई होती थी, इसलिए प्रेशर कम होने की जांच ही नहीं हो पायी, जिससे लीकेज का पता चलता और जब तक पता चला, तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। बस्ती के लोग कई दिनों तक खराब पानी को लेकर बार-बार शिकायत करते रहे, सरकारी अधिकारियों और अपने चुने हुए पार्षद से लेकर महापौर तक हरेक के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन गरीब बस्तीवालों की कौन सुने? वोट मिल जाने के बाद उनका क्या काम?

### दुर्घटना नहीं, गरीबों की अनदेखी

भागीरथपुरा त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही ढांचागत अनदेखी का परिणाम है। इस इलाके की ज्यादातर पाइप लाइनें 1993-94 में एक विदेशी सहायता प्राप्त झुग्गी विस्तार परियोजना के तहत बिछायी गयी थीं। इनमें से कई एस्बेस्टस-सीमेंट की थीं, जो झड़ने पर जानलेवा रेशे छोड़ती हैं। औद्योगिक बेल्ट के करीब होने के कारण जमीन के नीचे का पानी रासायनिक प्रदूषण की भेंट चढ़ चुका है, जिससे हैंड पंपों और कुओं का पानी जहरीला और पीने लायक नहीं रहा। 2008 में प्रोजेक्ट उदय (फेज-III) के तहत नर्मदा से 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी इंदौर की प्रणाली में जोड़ा गया। लेकिन पूरे शहर में बुनियादी ढांचे का समान रूप से आधुनिकीकरण करने की बजाय, पॉश कॉलोनियों और नये इलाकों में निरंतर सप्लाई के लिए आधुनिक एचडीपीई ट्रंक पाइप लाइनें और पुराने और गरीब इलाकों में बढ़ी हुई जनसंख्या का भार और बढ़े हुए प्रेशर को झेलने में अक्षम जर्जर धातु पाइप लाइनों के साथ इंदौर एक दोहरी व्यवस्था में बदल गया ।

2018 की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में इंदौर नगर निगम के ज्यादातर जल नमूनों में फीकल कोलिफॉर्म और अन्य प्रदूषक तत्व पाये गये थे। जबकि इंदौर नगर निगम के बजट का 25-30% हिस्सा पानी और सफाई पर खर्च होता है। एडीबी, स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत और अमृत 2.0 से हजारों करोड़ रुपये आये, जिसमें 1,073 करोड़ रुपये का निजी संचालन और रखरखाव ठेका भी शामिल है। पर गरीबों के कुछ काम न आया। नवंबर 2022 में भागीरथपुरा तक की पाइप लाइन बदलने के लिए 2.38 करोड़ रुपये की पुनर्विकास परियोजना स्वीकृत हो चुकी थी, टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन 3 साल तक इन फाइलों पर अफसर सत्तापक्ष के किस ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कुंडली मारे बैठे रहे, यह जांच का विषय है।

जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक टिप्पणी की कि "अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है।" अदालत ने अधिकारियों को उनके सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रहने के लिए फटकार लगायी और तुरंत सुरक्षित पानी की आपूर्ति, पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, दीर्घकालिक निवारक व सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने वही टिप्पणी की, जो जनता पहले से जानती थी–कि इस हादसे को रोका जा सकता था।

### फोकट का सवाल

अगर दूषित पानी प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है, तो इनकी प्रतिक्रिया नैतिक दिवालियेपन को उजागर करती है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीज द्वारा सार्वजनिक आश्वासनों के बावजूद, कई परिवारों ने मुआवजा न मिलने की शिकायत की। जब इस पर सवाल उठाये गये, तो जवाबदेही की बजाय मंत्री ने पत्रकारों को यह कहकर टाल दिया-"फोकट सवाल मत पूछो।" यह टिप्पणी उस व्यापक उदासीन संस्कृति का प्रतीक थी, जहां गरीबों की मौतों को असुविधा और सार्वजनिक निगरानी को बोझ समझा जाता है। इस लापरवाही और भ्रष्टाचार का खामियाजा 30 मासूम गरीबों ने अपनी जान देकर चुकाया। और सरकार ने गरीबों की जान की क्या कीमत लगाई? महज 2 लाख का मुआवजा! इसे कुछ परिजनों ने तो मंत्री विजयवर्गीज के मुंह पर यह कहकर फेंक मारा कि 2 साल से जब हम गटर का पानी पीने को मजबूर थे, तब आप कहां थे?

गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम पर पिछले 25 वर्षों से भाजपा काबिज है। साथ ही 2018-23 के अपवाद को छोड़कर इस क्षेत्र की विधानसभा पर भी भाजपा दशकों से काबिज है और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीज विधायक हैं और स्थानीय वार्ड 10 में पार्षद भी भाजपा का ही है। यह क्षेत्र दूषित पानी की समस्या से पिछले 25-30 साल से बुरी तरह जूझता रहा है।

20 साल से प्रदेश की सत्ता पर भी काबिज भाजपा सरकार ने घटना के बाद कुछ निलंबन और तबादले किये, पर गंभीर कार्रवाई से ज्यादा वे दिखावटी लगे। क्योंकि कुछ अधिकारियों को बाद में मलाईदार पदों पर नियुक्त कर दिया गया, जिससे यह धारणा और मजबूत हुई कि जवाबदेही वास्तविक नहीं, केवल औपचारिक है। विडंबना यह है कि जब भागीरथपुरा में मौतें हो ही रही हैं, तब संयोग से इन्हीं मंत्री जी के पूर्व संसदीय क्षेत्र इंदौर की तहसील महू में भी 23 जनवरी को दूषित पेयजल की ऐसी ही घटना सामने आयी, जहां 27 से ज्यादा लोग बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हो गए और वहां भी शिकायतें लंबे समय से अनसुनी थीं। दोनों घटनाएं बताती हैं कि लंबे समय तक शहर और प्रदेश में एक ही राजनीतिक पार्टी पर भरोसा जताने के बावजूद बुनियादी पर्यावरणीय सुरक्षा और पीने के शुद्ध पानी जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं।

भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुरूप, जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21) केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। स्वच्छ पेयजल इस अधिकार की बुनियाद है। जब राज्य दूषित पानी उपलब्ध कराता है, तो वह न केवल जनता के भरोसे को तोड़ता है, बल्कि संविधान की गारंटी का भी उल्लंघन करता है। इसलिए इंदौर जल संकट केवल नगर निगम की नाकामी ही नहीं, बल्कि संविधान का भी उल्लंघन है। इंदौर कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उस खतरे की एक चेतावनी है, जिसे केंद्रीय भूजल बोर्ड कई सालों से देता आ रहा है।

### अमृतकाल में नलों में विष

बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 20% से ज्यादा जिलों में भूजल नाइट्रेट से दूषित है, 9% में अत्यधिक फ्लोराइड है और कई राज्यों में आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन के खतरनाक स्तर पाये गये हैं। पूरे भारत में 6.6 करोड़ लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। गंगा पट्टी में पड़ने वाले उ.प्र, बिहार और बंगाल के तमाम जिले आर्सेनिक के कारण कैंसर के सघन क्षेत्र बन चुके हैं। नाइट्रेट दूषण से शिशुओं में "ब्लू बेबी सिंड्रोम" के मामले बढ़े हैं। यूरेनियम व भारी धातुएं दीर्घकालिक अंग क्षति व तंत्रिका संबंधी रोग पैदा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुधपुर से लेकर ओडिशा के भुवनेश्वर तक, भूजल एक खामोश हत्यारा बन चुका है। सबसे गरीब लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं।

भागीरथपुरा की त्रासदी ने यह मिथक तोड़ दिया है कि पुरस्कार सुरक्षा की गारंटी होते हैं। जर्जर पाइप लाइन, अनसुनी चेतावनियों और निष्ठुर शासन की भरपाई साफ सड़कें और चमकदार रैंकिंग नहीं कर सकतीं। इंदौर का संकट एक राष्ट्रीय आईना है। यह एक सरल-सा सवाल पूछता है। अगर नागरिक अपने नलों से सुरक्षित पानी नहीं पी सकते, तो ये किसका विकास है और किस कीमत पर?

### पेयजल बना बाजारू माल

स्वच्छ पेयजल न तो कोई विलासिता है, न कोई एहसान, और न ही कोई बाजारू माल। यह एक संवैधानिक अधिकार और राज्य की बाध्यकारी जिम्मेदारी है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारत के 21 प्रमुख शहरों के नलों का पानी पीने के लिए असुरक्षित पाया गया है। देश में लगभग 21% संक्रामक बीमारियां पानी से होती हैं। सरकार की काहिली से पानी हकीकत में एक बाजारू माल ही बन चुका है। देश में बोतलबंद पानी का बाजार 15% से 20% की सालाना दर से बढ़ रहा है। 2023 तक इसका मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया था। 20-लीटर के जार पर निर्भर एक औसत भारतीय परिवार पानी पर हर महीने 600 रुपये से 1,500 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करने को मजबूर है। जहां यह कम आय वाले लोगों के लिए एक बड़ा भारी बोझ है, लेकिन गरीबों के लिए सीधी मौत है!

जब तक लोग सरकारों से जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक भागीरथपुरा जैसे हादसे विनाशकारी तरीके से चुपचाप दोहराये जाते रहेंगे। यह 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते नागरिकों के लिए जागने और उसी संविधान में दिये गये अधिकारों के क्रियान्वयन पर सरकार से सवाल पूछने और उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करने का वक्त है। ●

## कॉमरेड प्रहलाद सिंह ने अंतिम सांस ली

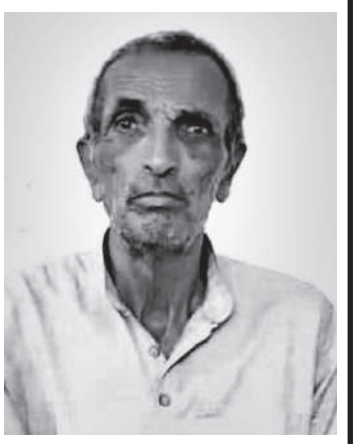

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता बुजुर्ग कॉमरेड प्रहलाद सिंह के निधन पर 26 फरवरी 2026 को उनके पैतक गांव खेड़ी मानाजात, जिला सोनीपत (हरियाणा ) में शोक सभा की गई।

शोक सभा में श्रद्धांजलि देते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिवमंडल के सदस्य कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि कॉमरेड प्रहलाद सिंह ने जैसे ही महान मार्क्सवादी चिंतक एवं एसयूसीआई (सी) पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के साहित्य को पढ़ा, जाना और समझा, तभी से वे पार्टी के झंडे तले सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में जुट गए। वैचारिक रूप से वे बहुत ही मजबूत इन्सान थे। वे बीमार होने के बावजूद आंदोलन में हिस्सा लेते थे। वे हमेशा ही पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को महत्व देते थे। वे अपने गांव व आसपास के गांवों में कॉमरेड शिवदास घोष की विचारधारा के प्रचार-प्रसार में हिस्सा लेते थे। उनके निधन से पार्टी को एक मजबूत कार्यकर्ता जाने की जो क्षति हुई है, उसे हम सबको मिलजुलकर पूरा करने का संकल्प लेना होगा। देश में कायम पूंजीवादी व्यवस्था आज लोगों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात, उल्टे जीवन के हर क्षेत्र में घनघोर संकट पैदा कर रही है। शराब समेत तमाम तरह के नशे, अश्लीलता, सैक्स विकृति व अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लोगों की एकता को तहस-नहस करने के लिए जात-पात, धार्मिक अंधविश्वास, परस्पर वैमनस्य, घोर रूढ़िवाद, कुसंस्कार और पुरानी सड़ी-गली सोच को प्रचारित किया जा रहा है।

श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष कॉमरेड हंसराज राणा ने कहा कि किसान-मजदूरों की आवाज को प्रहलाद जी ने हमेशा ऊंचा रखा। उनको यह पक्का भरोसा था कि एक ना एक दिन देश की मेहनतकश जनता शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक देगी और समाजवाद कायम किया जाएगा। एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश, एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड देवेंद्र सिंह, कॉमरेड भारत, कॉमरेड जयभगवान, कॉमरेड जयकरण दहिया, कॉमरेड प्रताप सिंह, कॉमरेड अजीत सिंह, कॉमरेड बिशम्भर, कॉमरेड ईश्वर सिंह, कॉमरेड ऋषिपाल आदि सभी ने दिवंगत कॉमरेड को श्रद्धांजलि दी।

**कॉमरेड प्रहलाद सिंह लाल सलाम**

## दूषित पेयजल पीने से हुई दर्दनाक मौतों पर व्यक्त किया गहरा दुःख

**गुरुग्राम (हरियाणा) :** एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने 17 फरवरी को जारी प्रेस बयान में पलवल जिला के हथीन उपमंडल के एक गांव छयासा में दूषित एवं जहरीला पेयजल पीने से 15 दिन में 12 नागरिकों की हुई दर्दनाक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

कॉमरेड सिंह ने कहा कि नागरिकों को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं करवा पाना किसी भी सरकार के लिए डूब मरने की बात है। एक ही गांव में एक के बाद एक मौत होती रही और सरकार इससे बेखबर रही। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, आपराधिक लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। हर मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। मौत के सिलसिले को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं और इस बात की जांच भी हो कि पानी के दूषित और जहरीला होने के पीछे क्या कारण हैं और जनता को सच्चाई से वाकिफ कराया जाए।

## केन्द्रीय बजट....

(पृष्ठ 2 का शेष)

यानी अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में लगभग 92% मजदूर अक्सर घोषित न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं और उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। हालांकि ताजा आर्थिक सर्वेक्षण में रोजगार के बारे में चिंता जतायी गई है, लेकिन बजट में इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

वैसे, 2024 के बजट में वित्त मंत्री ने एक नई 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम' की घोषणा की थी, जिसका मकसद "भारत की टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देना" था। कहा गया था कि यह कार्यक्रम युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में असल जिंदगी के बिजनेस माहौल से रूबरू करायेगा, जिससे उन्हें कीमती कौशल और काम का अनुभव हासिल करने में मदद मिलेगी"। लेकिन उसके बाद के दो बजटों में, इस स्कीम के नतीजों का कोई जिक्र नहीं किया गया। संसद में दिये गए आंकड़ों के आधार पर लगभग 16,000 से 16,060 उम्मीदवार इंटर्नशिप में शामिल हुए थे, जिसमें नवंबर 2025 के आखिर तक कम दिलचस्पी (5 साल में 1 करोड़ भर्ती का दावा) और ज्यादा पछतावा देखने को मिल रहा था। 2023 के बीच तक, भारत में केंद्र सरकार के अलग-अलग महकमों में लगभग 9.64 लाख खाली पद थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर पद या तो अभी भी खाली हैं या खत्म हो चुके हैं। एक आरटीआई के जवाब के मुताबिक, 2023 के बीच तक, भारतीय रेलवे में 2.74 लाख (274,580) से ज्यादा नॉन-गजटेड, ग्रुप बी के पद खाली थे। इन खाली पदों में जरूरी सुरक्षा-संबंधी पद शामिल हैं, जिनमें सुरक्षा प्रबंधन की श्रेणी में 1 लाख 70000 से ज्यादा पद भी हैं। अभी क्या स्थिति है, यह कोई नहीं जानता। बजट में वित्त वर्ष 2026-'27 के लिए रेलवे को 2.9 लाख करोड़ रुपये दिये गए। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल खाली पड़े पदों को स्थायी नियुक्तियों के आधार पर भरने, यात्रा की सुरक्षा का रखरखाव सुधारने, जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जायेगा या इसे महंगी अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने में खर्च किया जाएगा, जिसका किराया सिर्फ कुछ अमीर लोग ही वहन कर सकते हैं?

### रक्षा खर्च बढ़ा और सामाजिक कल्याण के बजट आवंटन में कटौती

बजट 2026 में खाने, उर्वरक और ईंधन सब्सिडी में 4.47% की कटौती की गई। लेकिन इसने सैन्य खर्च/आवंटन को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि खत्म होता पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के लिए और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी ओर, सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए बजट आवंटन कम कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए बजट में तय 67,000 करोड़ रुपये की जगह सिर्फ 17,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। हाउसिंग स्कीम (पीएमएवाई) के लिए 54,832 करोड़ रुपये की जगह 32,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। इसी तरह, केंद्र द्वारा प्रायोजित दर्जनों योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की बड़ी योजनाओं के लिए बजट आवंटन से कम था। पिछले कुछ सालों में कुल आवंटन के प्रतिशत के तौर पर कुल मिलाकर शिक्षा बजट में गिरावट आयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की जीडीपी का 6% शिक्षा को देने की सिफारिश के मुकाबले, केंद्र सरकार का शिक्षा पर बजट आवंटन जीडीपी का 0.6% होने का अनुमान है। साथ ही, अल्पसंख्यक शिक्षा कोष में 92% की कटौती देखी गई है, जो 678 करोड़ रुपये से घटकर 55 करोड़ रुपये रह गया है। इसके अलावा, बजट में शिक्षा-से- रोजगार-और-उद्यम (ई2ई) स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव है ताकि शिक्षा के नतीजों को श्रम बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ा जा सके और वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाया जा सके, जिससे शिक्षा से उसका मतलब छीनने का उसका मकसद पक्का हो सके।

### डिलीवरी की समयसीमा - बदलता गोलपोस्ट

एक और बात ध्यान देने लायक है। 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की किस्मत बदलने के लिए कुछ साल की मोहलत और देने की फरियाद की थी। 2016 में खतरनाक नोटबंदी की घोषणा के बाद, उन्होंने सकारात्मक नतीजे दिखाने के लिए 50 दिन मांगे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वे लोगों द्वारा दी जाने वाली किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 2017 में यह भी कहा था कि पांच साल में (यानी 2017 से 2022 तक), किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए डिलीवरी के लिए उनकी समयसीमा गोलपोस्ट बदलने जैसी थी।

अब, उन्होंने और उनकी सरकार ने समयसीमा 2047 तक बढ़ा दी है। इसलिए अगले 20 सालों में अपने वादों से मुकरने के लिए कोई उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा पायेगा। सच में अविश्वसनीय!

बजट की एक खास बात केंद्रीय पूंजीगत खर्च का लगातार बढ़ना है, जो अब 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर है- ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, फ्लाईओवर, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, एनर्जी सिस्टम और इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यह एक सोचे-समझे विकास मॉडल को दिखाता है। इस बजट ने टैक्स फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्रों) में उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने की इजाजत दी है। इससे किसे फायदा हो रहा है? एकाधिकारी पूंजीपति घरानों और बड़े ठेकेदारों को, जिन्हें ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन फ्लाईओवरों के नीचे रहने वालों, अपने घर-बार से बेदखलकर निकाले गये भूखे फुटपाथ वासियों का क्या? कोई जवाब नहीं मिलेगा। उपभोग या तबादले के जरिये सीधे मांग बढ़ाने की बजाय, सरकार संसाधनों को फिजिकल और उत्पादक परिसम्पत्तियों में लगाती है ताकि निजी निवेशक आयें और लंबी अवधि की उत्पादकता बढ़े।

### कुछ होते हैं कामयाब, कुछ जाते हैं पिछड़

कुछ खबरों के मुताबिक, धन-दौलत में असमानता सौ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी है। 248 अरबपतियों की कुल धन-दौलत (2025 की रिपोर्ट के मुताबिक) लगभग 98 लाख करोड़ रुपये है, यानी जीडीपी का 1/3 हिस्सा। भारत की ऊपर वाली 10% आबादी के पास देश की 57% आमदनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारत में कॉर्पोरेट मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 21 में 2.5 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 7.1 ट्रिलियन रुपये हो गया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने 100 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का 16.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है, जिनमें से ज्यादातर गुजरात की हैं। साथ ही, मौजूदा बजट में, टैक्स डिफॉल्टरों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और जेल जाने की बजाय उन्हें पैसे का मुआवजा देने का मौका दे दिया गया है।

तो, 'अमृतकाल' में 2030 तक 7 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनने का जो तथाकथित विकास का अनुमान है, उसका फायदा बड़े-बड़े व्यापारियों को ही होगा। अभी, अंबानी और अडानी की कुल सम्पत्ति क्रमश: 9.10 लाख करोड़ रुपये और 8.14 लाख करोड़ रुपये है। कई मीडिया आउटलेटों की खबरों और समीक्षाओं से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश दौरों और उसके बाद उन देशों में अडानी ग्रुप की परियोजनाओं की प्रदर्शनी के बीच एक तगड़ा संबंध है। उदाहरण के लिए, 2015 में प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के बाद, अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए झारखंड में कोयले से चलने वाले 1,600 मेगावाट के बिजली प्लांट के लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित किया था। इसी तरह, ग्रुप ने 2018 में ड्रोन बनाने के लिए एल्बिट सिस्टम्स के साथ साझेदारी की और बाद में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के इजराइल दौरे के बाद 2022 में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया था। अक्टूबर 2023 में तंजानिया के राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे के बाद मई 2024 में अडानी को दार एस सलाम बंदरगाह पर एक टर्मिनल चलाने के लिए 30 साल की छूट मिली थी। केन्या, मिस्र, वियतनाम और इथियोपिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे में, भाजपा सरकार आखिरकार किसके लिए काम कर रही है? दु:ख-तकलीफों से घिरे आम लोगों के लिए या चंद बड़े कारोबारियों के लिए?

### आखिरी शब्द

इन दोनों अलग-अलग परिदृश्यों से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? सरकार बढ़ती गैर-बराबरी से पूरी तरह खुश है, जब तक मौके की बातें चलती रहें। यह भविष्य को ध्यान में रखने वाला मॉडल साफ तौर पर अलग-अलग है और प्रधानमंत्री मोदी जी समेत भाजपाई नेताओं और मंत्रियों द्वारा अक्सर दोहराये जाने वाले नारे "सबका साथ, सबका विकास" की खिल्ली उड़ाता है। बजट सिर्फ सपने बेचता है, उन्हें पूरा करने का कोई असली इरादा नहीं है।

जैसा कि हमारी केंद्रीय कमेटी के बयान में कहा गया है, "नागरिकों की 'जीवन की आसानी' के बारे में कोई चिंता दिखाने की बजाय व्यवसाय करने में आसानी पर ज्यादा जोर दिया गया।" इस नजरिये से, संकल्प बजट के "विकास और खुशहाली" जैसे बड़े-बड़े शब्द और आर्थिक सर्वेक्षण में "अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक्स मोमेंट में है, जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है" बकवास लगते हैं।

## भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

विमानों सहित करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदेगा। दोनों देशों की बातचीत में यह तय हुआ कि भारत अमेरिका से और ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा ताकि व्यापार घाटा कम हो सके। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ही भारत को सबसे ज्यादा तेल और गैस की आपूर्ति करेगा। ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि भारत को रूस से सस्ता तेल न खरीदकर अमेरिका के जरिये अमेरिका और वेनेजुएला का महंगा तेल खरीदना होगा। इतना ही नहीं, अब तक कानून यह था कि असैनिक परमाणु उत्पादन में कोई दुर्घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी रिएक्टर आपूर्ति करने वाली कंपनी की होती थी। सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दे दी है और नया कानून लाकर कंपनियों को दुर्घटना की जिम्मेदारी से छूट दे दी है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इसका लक्ष्य अमेरिकी कंपनियां ही हैं।

क्योंकि व्यापार समझौते के तहत, अमेरिकी कंपनियों को ही करोड़ों रुपये के रिएक्टरों की आपूर्ति का ठेका मिला है। दूसरी ओर, बिना किसी पूर्व अनुभव के रातों-रात खड़ी हुई अदानी की असैनिक परमाणु बिजली उत्पादन कंपनी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और उसे बिजली का व्यापार करने का अवसर प्रदान किया गया है। वहीं दूसरी ओर, लोकतंत्र के न्यूनतम मानदंडों को भी धता बताते हुए रात के अंधेरे में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले जाने के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने वहां के तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया है। भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रंप से उसी तेल के आयात की इजाजत मिली है। दरअसल, दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस समझौते का एकमात्र उद्देश्य भारत की जनता के हितों की बलि देकर भारतीय एकाधिकारी पूंजी के मुनाफे की रक्षा करना है।

### एकाधिकारी पूंजी का हित सर्वोपरि है, जनहित कहीं नहीं है

समझौते की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धोखा देने के उद्देश्य से कहा था कि यह समझौता पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। वास्तव में साम्राज्यवाद के लिए लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। पूंजी का निरंकुश हित ही साम्राज्यवादियों के लिए लोकतंत्र है। ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे वे मुनाफे के लिए न कर सकें। आज ताकतवर साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका का लक्ष्य सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में अपना पूर्ण वर्चस्व कायम करना है।

भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मामले में भी अमेरिका का लक्ष्य भारतीय पूंजी को ताकतवर अमेरिकी पूंजी पर निर्भरशील बनाना और भारतीय बाजार को अमेरिकी धनकुबेरों के उत्पादों को बेचने का एक खुला मैदान बनाना है। भारतीय पूंजीपति वर्ग का भी लक्ष्य अमेरिकी निकटता का लाभ उठाकर खुद को क्षेत्रीय साम्राज्यवादी शक्ति से विश्व साम्राज्यवादी शक्ति के स्तर तक ले जाना है और भारतीय निवेश पूंजी के लिए अपेक्षाकृत कमजोर देशों के नये-नये बाजारों में प्रवेश पाने के लिए अमेरिकी समर्थन हासिल करना है। कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में एकाधिकारी पूंजी का हित ही मुख्य है, जनहित कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, एकाधिकारी पूंजीपतियों के हितों को साधने में घरेलू लघु एवं मंझोले पूंजीपति वर्ग के हितों के साथ-साथ जनहित की भी बलि दे दी गयी है। ■

## भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री हादसा सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा

**जयपुर (राजस्थान):** एसयूसीआई (सी) तैयारी कमेटी, राजस्थान के राज्य सचिव कॉमरेड रामदयाल ने 16 फरवरी को जारी प्रेस बयान में कहा कि दिनांक 16 फरवरी को भिवाड़ी, जिला खैरथल, राजस्थान में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 8 मजदूर जिन्दा जल गए तथा 4 मजदूरों की हालत गम्भीर है। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों की लाश को पहचानना भी नामुमकिन था। सरकारी तंत्र की लापरवाही से हुई इस दुर्घटना पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये तथा घायलों को 2-2 लाख मुआवजे के रूप में दे और घायलों का निशुल्क इलाज कराये। साथ ही साथ दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दे।

**समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण**

**घोषणा**

**फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)**

प्रकाशन का स्थान : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि : पाक्षिक
मुद्रक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
उन व्यक्तियों के नाम एवं पते, जो अखबार के स्वामी हैं या जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं: सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इंडिया(कम्युनिस्ट)

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। हस्ताक्षर

सत्यवान

दिनांक : 5 मार्च, 2026 (प्रकाशक के हस्ताक्षर)

PRGI Regn. No. 43022



# 'भारती-नारी से नारायणी' कन्वेंशन में जाने के यूजीसी के फरमान की ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी ने की निंदा

यूजीसी के भारती-नारी से नारायणी पर उठाये गए कदम की निंदा करते हुए ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) के अखिल भारतीय महासचिव प्रो. तरुण कांति नस्कर ने 17 फरवरी को जारी प्रेस में एक बयान में कहा कि यूजीसी ने आरएसएस से जुड़े संगठनों, जैसे कि भारतीय विद्वत परिषद (बीवीपी) और राष्ट्रीय सेविका समिति (आरएसएस) के पत्रों के आधार पर एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआईज) से 7-8 मार्च 2026 को होने वाले "भारती-नारी से नारायणी" नामक कन्वेंशन में सक्रिय रूप से समर्थन करने और हिस्सा लेने की अपील की है। यूजीसी ने सभी महिला वाइस-चांसलर से भी हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। इसने उच्च शिक्षा संस्थानों से कन्वेंशन में शामिल होने के लिए हर संस्थान से दो फैकल्टी मेम्बरों को नामित करने का भी अनुरोध किया है। यूजीसी, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को एक्रेडिटेशन देने और उन्हें फंड देने वाली एक स्वायत्त बॉडी है, यह फरमन जारी करके असल में आरएसएस की पिट्ठू बन गयी है।

इन दोनों संगठनों के पत्रों में जिन आठ थीमों, जैसे "जड़ें मजबूत करना" या "सफलता की कहानियां" का जिक्र है, वे उन मुद्दों पर आधारित हैं, जो महिलाओं को "संरक्षणवादी नजरिया अपनाने", "परंपराओं की रक्षा करने", "परिवारों में शिक्षा का समर्थन करने" वगैरह के लिए परिवार के पास वापस जाने को बढ़ावा देती हैं, जिनका महिलाओं को आधुनिक जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने से कोई लेना-देना नहीं है। ये महिलाओं के लिए 'मनुवादी' नारों जैसे 'रसोई में वापस जाओ' और 'बच्चे का पालन-पोषण करो' से मिलते-जुलते हैं। असल में भाजपा और आरएसएस इन मनुवादी विचारों की समर्थक हैं।

यूजीसी के इस फरमान की एआईएसईसी कड़ी निंदा करती है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

# बिना किसी उकसावे के ईरान पर अमेरिका-इजरायल जोड़ी के सैन्य हमले की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निंदा

**प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हत्यारे इजरायली प्रधानमंत्री को भाई कहे जाने पर धिक्कारा**

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 28 फरवरी 2026 को जारी बयान में कहा :

"एक निराधार बहाने से "निवारक हमले" के नाम पर जायोनी इजराइल द्वारा ईरान पर किये गए सबसे भीषण सैन्य हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, जो अमेरिकी साम्राज्यवादियों की पूरी शह और समर्थन से किये गये एक खुले सैन्य हमले के सिवा और कुछ नहीं है। दरअसल यह अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा ईरान पर किया गया एक खुला हमला है। हम ईरान के खिलाफ इस नग्न हमले को तत्काल रोकने की मांग करते हैं।

यह बहुत ही तिरस्करणीय बात है कि यह घटना भारतीय प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे के ठीक बाद हुई, जहां उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष को आतंकवाद के खिलाफ युद्धकर्ता का सर्टीफिकेट दिया था।

हम दुनिया के लोगों से आह्वान करते हैं कि संप्रभु ईरान के खिलाफ अपने नग्न आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों और जायोनी इजराइल को मजबूर करने के लिए वे आगे आएं और जोरदार जन आंदोलन खड़ा करें।

हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार को तुरंत जायोनी इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए।

# आशाओं का मानदेय बढ़ाने और सरकार से अधूरे वादे पूरे करने की एआईयूटीयूसी से संबद्ध आशा यूनियन ने की मांग

**बेंगलुरु: मानदेय वृद्धि और अन्य लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरी आशाएं**

**बेंगलुरु (कर्नाटक) :** एआईयूटीयूसी से संबद्ध आशा यूनियन के बैनर तले 26 फरवरी को यहां फ्रीडम पार्क में आशा वर्कर्स ने राज्य-स्तरीय विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यूनियन ने आशाओं का मानदेय बढ़ाने और छंटनी रोकने की मांग की।

आगामी राज्य बजट से पहले, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बड़ा राज्य-स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय बढ़ाने, लंबित मांगों को पूरा करने और 'रेशनलाइजेशन' की आड़ में 7,000 आशा वर्कर्स को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की।

इस मौके पर मुख्य वक्ता कर्नाटक राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की राज्य सचिव कॉमरेड डी. नागलक्ष्मी ने कहा कि 7 से 10 जनवरी, 2025 तक हुए दिन-रात के धरने-विरोध प्रदर्शन के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री ने चौथे दिन यूनियन की पदाधिकारियों से खुद वादा किया था कि आशा वर्कर्स को कम से कम 10,000 रुपये महीने मानदेय गारंटी के साथ दिया जायेगा। आंगनवाड़ी और मिड-डे मील वर्कर्स की तरह 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के उनके आश्वासन पर आंदोलन वापस ले लिया गया था। मार्च 2025 के बजट में आशा वर्कर्स को पूरी तरह से बाहर रखा गया। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का वादा किया गया था। लेकिन 14 महीने बाद भी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई वार्ता बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है, जिससे हमें वापस सड़कों पर आना पड़ रहा है।

सरकारों की उदासीनता की आलोचना करते हुए मुख्य अतिथि एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड के. सोमशेखर ने कहा कि आशा वर्कर्स के इंसेंटिव में सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार की वादा की गयी 1,500 रुपये की बढ़ोतरी केंद्रीय बजट से गायब थी और मुख्यमंत्री भी अपना वादा भूल गए लगते हैं। आशाओं के भुगतान को आरसीएच पोर्टल से जोड़ने से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें खोखले वादों से वर्कर्स को छल रही हैं।

आशाओं की छंटनी के विभागीय कदम की निंदा करते हुए आशा यूनियन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड के. सोमशेखर यादगिरी ने कहा कि युक्तीकरण (रेशनलाइजेशन) के नाम पर हजारों आशा वर्कर्स को नौकरी से निकालने का आदेश केंद्र सरकार की हिदायतों का सरासर उल्लंघन है। भारत में किसी दूसरे राज्य ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। आबादी के आधार पर रेशनलाइज करने की इस गैर-कानूनी कोशिश से आशा वर्कर्स में भारी रोष है। राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड एम. उमादेवी ने बताया कि ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी खराबी की वजह से वर्कर्स को पैसे का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग मूल प्रशासनिक दिक्कतों को हल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं को बार-बार प्रतिवाद करना पड़ रहा है।

इस प्रतिवाद सभा को ऑल इण्डिया महिला सांस्कतिक संगठन (एआईएमएसएस) की राज्य सचिव शोभा और मेडिकल सर्विस सेंटर (एमएससी) के राज्य उपाध्यक्ष डॉ. के.एस. गंगाधर ने समर्थन किया।

बजट-पूर्व मांगें थीं कि केंद्र और राज्य के हिस्से को मिलाकर हर महीने 15,000 रुपये बंधा मासिक मानदेय दिया जाए। घोषणपत्र में किये गये वादे के मुताबिक मार्च 2026 के बजट में राज्य की ओर से दिये जाने वाले मानदेय को तुरंत 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाए। पश्चिम बंगाल मॉडल की तरह सेवानिवृत्त आशाओं को सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर एकमुश्त रकम (ग्रेच्युटी) दी जाए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक मेडिकल सहायता कोष बनाया जाए और भुगतान पक्का किया जाए और गंभीर बीमारियों से ठीक हो रहे वर्कर्स को 3 महीने का नियत मानदेय दें।

प्रशासनिक मांगें ये थीं कि छंटनी रोकें और रेशनलाइजेशन के तहत आशा वर्कर्स को हटाने की कार्रवाई तुरंत बंद करें। सही वेतन सहित आशा फैसिलिटेटर्स की सेवा जारी रखें और साल 2024-25 के लिए हर महीने 1,500 रुपये का बकाया एरियर जारी करें। टीबी, टीबी-I व दूसरे कॉम्पोनेंटों से जुड़े सभी पेंडिंग ड्यूज के बैकलॉग क्लियर करें। 'राज्य सरकार गारंटी' सर्वेक्षण के लिए वादा किया गया 1,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता जारी करें।

डिपार्टमेंट के अधिकारियों का जवाब था कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निदेशक डॉ. वसंत कुमार ने आंदोलनकारी आशाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि विभाग ने सरकार को इन मामलों में ये प्रस्ताव दिये हैं: महीने का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाना। मेडिकल खर्च के लिए एक कॉर्पस फंड बनाना। गंभीर बीमारियों के मामले में बहाल होने की 3 महीने की अवधि का मानदेय देना।

डॉ. प्रभुदेव गौड़ा, राज्य नोडल अधिकारी (आशा), भी मौजूद थे।

आशा वर्कर्स एसोसिएशन की राज्य कमेटी ने एलान किया कि अगर सरकार आने वाले बजट में इन प्रस्तावों और मांगों के लिए ठोस समाधान की घोषणा करने में नाकाम रहती है, तो पूरे राज्य में एक बड़ा संघर्ष छेड़ा जाएगा।

# पानीपत रिफाइनरी के आन्दोलनरत मजदूरों का एआईयूटीयूसी ने किया समर्थन

**पानीपत (हरियाणा) :** ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) हरियाणा प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने 24 फरवरी को जारी बयान में कहा कि पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी में रोजाना 8 घंटे से ज्यादा कार्य न लेने, कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं केंटीन की समुचित व्यवस्था, श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार, साप्ताहिक अवकाश आदि अपनी जायज मांगों को लेकर मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन में सीआईएसएफ द्वारा हस्तक्षेप व हवाई फायरिंग कर मजदूरों को खदेड़ने की घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि मजदूर अपनी बुनियादी एवं न्यायोचित मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगें अत्यंत सामान्य और श्रम कानूनों के अनुरूप हैं। मजदूरों की मांगें मानने की बजाय रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा ठेकेदारों के हित में मजदूरों की आवाज दबाने के लिए सीआईएसएफ बल का दुरुपयोग घोर अलोकतांत्रिक और अत्यंत निंदनीय है।

एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी ने रिफाइनरी प्रशासन एवं हरियाणा सरकार से निम्न मांगें तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की: रिफाइनरी प्लांट में ठेका प्रथा समाप्त की जाए। इसके सभी ठेका कर्मियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। खाना खाने के 1 घंटे के अवकाश सहित कार्यदिवस 8 घंटे से ज्यादा न हो। ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाए। मजदूरों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें तुरंत वापस ली जाएं। भविष्य में मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलनों पर दमनात्मक कार्रवाई न की जाए।

कॉमरेड हरिप्रकाश ने पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों से अपील की कि वे अपनी एकजुटता बनाये रखें, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखें।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
**Editor: Comrade Satyawan**, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**